www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 312 | जौनपुर शुक्रवार, 03 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

मल्लिकार्जुन खड़गे फिर बने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, किरेन रिजिजू ने दी बधाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उन्हें बधाई देते हुए संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति 26 जून 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि 'सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट, 1977' की धारा 2 के तहत राज्यसभा के सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। इसके बाद अधिनियम की धारा 9 के तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 26 जून से इस पद पर अधिसूचित कर दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अधिसूचित किए जाने पर हार्दिक बधाई। मैं सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने और संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं एवं मूल्यों को मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इच्छुक हूं।" मल्लिकार्जुन खड़गे का पिछला कार्यकाल 25 जून 2026 को समाप्त हो गया था।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टीवी डिबेट से बनाई दूरी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई न्यूज चौनल से नाराज है और उसने फैसला लिया है कि उसके प्रवक्ता तीन दिन तक किसी भी न्यूज चौनल की डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस का यह मौन सत्याग्रह होगा। वहीं, दूसरी ओर पार्टी ने पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया है, जिसे नेता संबोधित करेंगे।शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका कांग्रेस संगठन के प्रभारी महासचिव संजय कामले ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भूमि घोटाला प्रकरण को लेकर प्रदेशभर में व्यापक जनचर्चा है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सोशल मीडिया पर तथ्य, दस्तावेज और सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनभावनाओं के अनुरूप इस गंभीर विषय को न तो प्रसारित किया और न ही इस पर सार्थक टीवी बहस आयोजित की।कांग्रेस का मानना है कि जनता का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता तक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी के विरोध में तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी तीन दिनों तक मौन सत्याग्रह किया जाएगा।

समस्त शिवभक्तों को श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शुक्रवार को सुभाषित शेयर किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "समस्त शिवभक्तों को पावन–पुनीत श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं! बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की यह यात्रा आप सभी के जीवन में सुख–समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय बाबा बर्फानी!" इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जिनके स्वरूप को वाणी, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों के द्वारा, यहां तक कि कठोर तपस्याओं से भी नहीं जाना जा सकता, जो भक्तिभाव से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और नतमस्तक भक्तों के आश्रय हैं, उन दयालु भगवान की मैं नित्य आराधना करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 2 जुलाई गुरुवार को भी सुभाषित शेयर किया गया था। पीएम ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा था, "निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। जीवन में वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जो धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने एक श्लोक नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जो मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वह समृद्धि प्राप्त करता है, किंतु जो निष्क्रिय होकर बैठा रहता है, वह प्रगति से वंचित रह जाता है। निरंतर प्रयत्न करने वाले का भाग्य भी साथ देता है, इसलिए निरंतर कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। पीएम ने 1 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सुभाषित में लिखा था, "डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों की सफलता से भारतवर्ष को दुनियाभर में एक नई पहचान मिली है। इससे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की देशवासियों की संकल्पशक्ति का पता चलता है। जिसका हिंदी अर्थ है कि वह मनुष्य जिसकी विवेकपूर्ण बुद्धि वैज्ञानिक सारथि के समान जागरूक हो और जिसका मन संयमित हो, वह जीवन–पथ की जटिलताओं को पार कर परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है।

आधा किलो का आम देख मुस्कुराए सीएम योगीय किसानों को किया सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आम उत्पादकों से विभिन्न किस्मों की विशेषताओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में रखे करीब आधा किलो वजनी आम को देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा पड़े और दोनों हाथों में आम लेकर तस्वीर भी खिंचवाई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दो पेटी आम खरीदे। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का आम ब्रिटेन, यूएई, मलेशिया और कुवैत समेत कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक विशेष आम को ष्काकोरी ब्रांडष का नाम दिया गया है, जो देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तीन दिवसीय आम महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, रटौल, लखनऊ सफेदा, अल्फांसो, याकूती, बनाना मैंगो, नूरजहां, लालिमा और टॉमी एटकिंस जैसी प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। वहीं मोदी मैंगो और योगीराज आम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में आम से बने अचार, जूस, पल्प और अन्य उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एआई आधारित खेती, ई–कॉमर्स और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने रसायन–मुक्त उत्पादन, गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के अनुरूप आम तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की असली ताकत उसके किसान हैं ।

बंगाल के विधायकों से ओम बिड़ला बोले, समाधान खोजना ही एक आदर्श विधानसभा का लक्ष्य

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी आदर्श राज्य विधानसभा का मुख्य उद्देश्य सार्थक चर्चा करने और मुद्दों को पहचानने के अलावा, मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजना भी होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम (परिचय कार्यक्रम) के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आम लोगों को विधायक से बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। विधायक की भूमिका, मौजूदा कानून और लोगों की उम्मीदें व हालात, ये सभी राज्य के विकास से जुड़े हैं। इसलिए, एक आदर्श विधानसभा वह जगह है जहां समाधान खोजे जाते हैं, चर्चाएं होती हैं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। पुरानी सभी चर्चाओं और बहसों को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को सलाह दी कि वे राज्य विधानसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जानकारी पर आधारित चर्चाओं पर ध्यान दें और साथ ही सीखने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया में भी शामिल रहें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको जानकारी के आधार पर मुद्दों और विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। आपको अपनी टीम और देश का नेतृत्व करना चाहिए। आपको सीखना है और और अधिक सीखना है। आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीखने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। आपको उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के फायदे के लिए कुछ नया करना सीखना चाहिए जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्षेत्र, भाषा और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र सदैव सर्वोपरि है – उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सांसद डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े द्वारा युवाओं को सार्वजनिक नीति, सुशासन और संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए आरंभ किए गए दो महीने के इंटर्नशिप कार्यक्रम, एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों से गुरुवार को उपराष्ट्रपति भवन में संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने उन्हें नैतिकतापूर्ण आचरण अपनाते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित नेता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का आकलन अधिकार से नहीं, बल्कि विनम्रता, सत्यनिष्ठा और करुणा के साथ समाज की सेवा करने की क्षमता से होता है। उपराष्ट्रपति ने भारत की सभ्यतागत एकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत एक था, एक है और सदा एक रहेगा। प्रतिभागियों को क्षेत्र, भाषा और जाति से ऊपर उठने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यापत भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत ने हमेशा राष्ट्र को एकजुट बनाया है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। राधाकृष्णन ने 1960 के दशक में खाद्य पदार्थों की कमी से जूझते भारत के आगे बढकर विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में से एक बनने तक की परिवर्तनकारी यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि युवाओं को पिछली पीढ़ियों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को समझना चाहिए और राष्ट्र की विकास यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए। राधाकृष्णन ने एमपी लीड फेलोशिप को करियर आरंभ करने का आदर्श मंच बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को कक्षाओं से परे दुनिया का पता चलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और राष्ट्रीय नेताओं के साथ संवाद के अवसर मिलते हैं। उन्होंने योग्यता और निरंतर आत्म–सुधार को महत्व देते हुए फेलोशिप के प्रतिभागियों से उत्कृष्टता के लिए सदा प्रयास करने और राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को कहा। प्रशिक्षुओं की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि इनमें से कई लोग भविष्य में सार्वजनिक जीवन, प्रशासन और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे।

मध्य प्रदेश के किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच से करेंगे - मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। देश की अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी संभावित अल्पवर्षा के मद्देजनर राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य के किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच और उचित तैयारी से करेंगे। मुख्यमंत्री यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य संबंधित विभागों की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध तैयारी के अवसर के रूप में लिया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं, ताकि प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच और उचित तैयारी के साथ करे। समय पर सही निर्णय और विभागों के प्रभावी समन्वय से हम संभावित अल्प वर्षा के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर तथा कोदो–कुटकी जैसी मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये फसलें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने के साथ किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जल्दबाजी में बुआई नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। खेतों में पर्याप्त नमी बनने के बाद ही बुआई की जाए तथा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

फ्लाइंग व्हेल्स भारत में बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग हब, वित्त मंत्री सीतारमण से हुई अहम बैठक

फ्रांस, (एजेंसी)। फ्रांस की एयरोस्पेस लॉजिस्टिक्स कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स भारत में अपना विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगी। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पेरिस में कंपनी के अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगॉन के साथ बैठक कर निवेश और संभावित सहयोग पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। बैठक के दौरान सेबेस्टियन बोगॉन ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हेल्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी की तकनीक दूर–दराज और भू–आवेष्ठित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में मदद करती है तथा माल ढुलाई के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करती है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग व्हेल्स अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में स्थापित कर देश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी की भारत में निवेश की योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में फ्लाइंग व्हेल्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) और जहाज व विमान लीजिंग तथा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस (एमआरओ) से जुड़े नियामकीय ढांचे की जानकारी भी दी। गौरतलब है कि फ्लाइंग व्हेल्स और भारत के बीएलपी ग्रुप ने 2 अप्रैल 2026 को रणनीतिक साझेदारी के पहले चरण की घोषणा की थी।

सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा, विश्व बैंक के सहयोग से दिल्ली में शुरू होगी 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना शुरू करने जा रही है। यह पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली की वायु प्रदूषण मिटिगेशन प्लान को तेजी से लागू करना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और 'विकसित भारत 2047' के विजन में योगदान देना है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं है।

सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सीएम विजय का बड़ा कदम

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विभाग–वार समीक्षा बैठकों की एक बड़ी सीरीज शुरू की। इसका मकसद शॉर्ट–टर्म और लॉन्ग–टर्म गवर्नेंस रणनीतियां तैयार करना है। अधिकारियों को हर विभाग के लिए एक साल, तीन साल और पांच साल के व्यापक एक्शन प्लान बनाने का काम सौंपा गया है। 22 जुलाई तक चलने वाली इस समीक्षा प्रक्रिया में मुख्य सरकारी विभागों के कामकाज का आकलन करने, लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और आने वाले वर्षों में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए मापने योग्य लक्ष्य तय करने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने विभाग के कामकाज, चल रही कल्याणकारी योजनाओं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सहकारी संस्थाओं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपायों की समीक्षा की। अधिकारियों ने पब्लिक सर्विस को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए भविष्य की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। बैठक में फूड और सिविल सप्लाई मंत्री पी. वेंकटरमनन, कोऑपरेशन मंत्री वी. गांधीराज और वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन शामिल हुए। मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने वरिष्ठ नौकरशाहों और विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को विभाग के कामकाज और विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।सीएम विजय ने बाद में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा रेवेन्यू प्रशासन, आपदा की तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, भूमि प्रशासन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की राज्य की क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर केंद्रित थी। बैठक में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन ने वित्त मंत्री मैरी विल्सन के साथ भाग लिया। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की और भविष्य की पहलों के लिए प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की।

संपादकीय

छवि से बंध जाना सही सोच नहीं

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अपना महत्त्व है। इसलिए उन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन कृत्रिम ढंग से उनमें दर्जा बढ़ाने की कोशिशें हानिकारक हैं। फिर रैंकिंग्स में उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है। यह अच्छी खबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। 500 विश्वविद्यालयों की इस ताजा सूची में भारत की 54 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। इसमें भारत की नुमाइंदगी अब आईआईटी या आईआईएस जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई है। बल्कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राज्यों के विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थानों ने भी इसमें जगह बनाई है। हालांकि यह अप्रिय तथ्य अब भी कायम है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। टॉप 200 में भारत के सिर्फ तीन विश्वविद्यालय ही आए हैं। सबसे ऊपर 118वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली आई है। बहरहाल, शिक्षा संस्थानों के स्तर को जानने के लिए रैंकिंग्स भले एक प्रचलित माध्यम हों, लेकिन इनके आधार पर किसी देश में शिक्षा की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना सही नजरिया नहीं होगा। मसलन, क्यूएस रैंकिंग की यह एक बड़ी आलोचना है कि इसमें विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। इसका भार 40 प्रतिशत तक है। प्रतिष्ठा मनोगत पैमाना है, जो सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों की जानकारी एवं पूर्व–धारणाओं से तय होती है। एक अन्य पैमाना विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की उपस्थिति है। भारतीय विश्वविद्यालय इस पैमाने पर पिछड़ जाते हैं। इसलिए क्यूएस या ऐसी अन्य रैंकिंग्स में भारत की स्थिति अपने–आप में समस्या नहीं है। समस्या यूनिवर्सिटी शिक्षा तक सीमित वर्गों की पहुंच, वास्तविक अनुसंधान पर कम ध्यान, और जाने वाली शिक्षा का रोजगार बाजार से कमजोर संबंध हैं। इस ओर ध्यान देने के बजाय रैंकिंग में आगे बढ़ने की होड़ का खराब असर यह हुआ है कि विश्वविद्यालयों में प्रति फैकल्टी प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने और उन प्रकाशनों का आपस में उद्धरण देने जैसी विकृतियां उभरी हैं। इसलिए आवश्यकता रैंकिंग्स से आगे सोचने की है। इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए जीडीपी का अधिक हिस्सा आवंटित करना, शिक्षक–छात्र अनुपात सुधारना और शोध संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। वैश्विक शोध नेटवर्क से जुड़ने और संकाय आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। रैंकिंग्स को पूरी तरह ठुकराना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है।

सीजेपी के आंदोलन के पीछे साजिश

अजीत द्विवेदी

जिसको देखिए वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर संदेह कर रहा है। उससे जुड़े लोगों की पृष्ठभूमि खोजी जा रही है। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक समय में नरेंद्र मोदी का प्रशंसक था किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है और वह आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करता था। किसी को राहुल गांधी का विरोध करने वाला बताया जा रहा है तो किसी को ब्राह्मण विरोधी ठहराया जा रहा है। सोचें, युवाओं का एक समूह इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा उठा कर सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। लेकिन जरूरी मुद्दे उठाने में असफल रहे लोग उनकी पृष्ठभूमि निकाल कर उनको निशाना बना रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और तीनों प्रवक्ताओं सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका की पृष्ठभूमि खोज कर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम इन लोगों को युवाओं व छात्रों का एजेंडा हाईजैक करने के लिए भाजपा की ओर से प्लांट किया गया बता रहे है तो भाजपा के नेता सीजेपी की तुलना अन्ना हजारे व अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से कर रहे हैं और इसे अर्बन नक्सल समूह कह रहे हैं। सवाल है कि इस समूह और इसके आंदोलन को वर्तमान हालात से पैदा हुए असंतोष और युवाओं की बेचैनी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों नहीं माना जा सकता है? यह मानने में क्या समस्या है कि आज किशोर और युवा परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों और नौकरी व रोजगार की घटती संभावनाओं की वजह से परेशान हैं और इसलिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला तो वे वहां से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं? अभिजीत दीपके या सीजेपी से जुड़े दूसरे लोगों ने किशोरों और युवाओं को अपनी नाराजगी और असंतोष जाहिर करने का एक मंच दिया है, जहां से वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत समस्या को उठा रहे हैं। सीजेपी के लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता बहाल करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन मांगों से भला विपक्ष की पार्टी या नेता को क्या समस्या हो सकती है? युवाओं का यह समूह भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को भी निशाना बना रहा है। इसलिए आप इसे सांप्रदायिक भी नहीं कह सकते हैं। तभी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजेपी के आंदोलन को विपक्ष, खास कर कांग्रेस पार्टी अपनी विफलता के तौर पर देख रही हो और इस वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा हो? यह संभव है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी इसलिए सीजेपी को मौका मिला। अगर कांग्रेस युवाओं के असंतोष को आवाज दे रही होती और उस असंतोष को प्रकट करने का मंच दे रही होती तो शायद सीजेपी जैसे किसी समूह की जरुरत नहीं पड़ती। ध्यान रहे सीजेपी अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बना एक अकाउंट भर है। उसके पास न कोई संगठन है, न कोई बड़ा चेहरा है और न किसी राजनीतिक अभियान को चलाने का प्रशिक्षण या अनुभव है। फिर भी उस मंच से करोड़ों युवा जुड़े और उसके आह्वान पर हजारों लोग 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। कहने को कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी और प्रभावित छात्रों से मुलाकात की लेकिन यह समझने की जरुरत है कि समस्या जितनी बड़ी है उसके मुकाबले कांग्रेस का प्रयास बहुत छोटा और सुविधाजनक है। ड्राइंग रूम में बैठ कर 18 साल के छात्र से बात करना और उसकी वीडियो साझा करके सरकार पर हमला करना बहुत आसान है। बहरहाल, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों की संख्या असल में कितनी थी, किसके साथ ज्यादा भीड़ आई, किसका भाषण कैसा हुआ, कितनी देर प्रदर्शन चला, कौन जल्दी चला गया, किसको गर्मी लग रही थी और किसको एसी में बैठना था इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जंतर मंतर पर यह तस्वीर दिखी कि हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिनमें परीक्षा की गड़बड़ियों और पेपर लीक से परेशान छात्र थे तो नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवा भी थे और रोजगार की घटती संभावना से बेचैन अधेड़ लोग भी थे। मुख्यधारा की मीडिया ने भले इसका बहिष्कार किया लेकिन राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के तमाम छोटे बड़े यूट्यूबर वहां मौजूद थे। उन्होंने इसे अपने अपने हिसाब से कवर किया और देश के हर हिस्से में करोड़ों लोगों ने इसे देखा। किसी राजनीतिक या सामाजिक घटनाक्रम में लोगों में ऐसी उत्सुकता अरसे बाद देखने को मिली। किसान आंदोलन के बाद पहली बार ऐसे संगठित प्रतिरोध का स्वर पहली बार सुनाई दिया। अभी इसको इसी रूप में देखने की जरुरत है, जब तक कि कोई दूसरी बात प्रमाणित नहीं हो जाती है।

भाई–बहन की जोड़ी मोदी–ताकाइची ने रचा इतिहास

नीरज

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी "छोटी बहन" बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना "बड़े भाई" बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की साफ्टवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली "यूनिकॉर्न" के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों देश क्वॉड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक बदलते सामरिक समीकरणों के बीच यह रक्षा सहयोग विशेष महत्व रखता है। साथ ही भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, धातु और उर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की, जिसके तहत रुपये और येन में सीधे व्यापार की संभावना पर काम होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी। साथ ही जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता आधारित तकनीक मिलकर विश्व को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ ही भारत जापान जैव गैस पहल के अंतर्गत भारत में एक हजार जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखा जाये तो यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। चीन की सैन्य सक्रियता, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत और जापान को और करीब ला दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता

को लेकर उठते सवालों के बीच टोक्यो अब नई दिल्ली को अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में देख रहा है। भारत भी जापान को केवल निवेशक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों ने भी इस साझेदारी को मजबूती दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी की जापान यात्राओं से शुरू हुआ यह संबंध अब व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। वर्तमान वार्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान संबंध एशिया की सबसे निर्णायक रणनीतिक धुरी बन सकते हैं। देखा जाये तो भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देगा। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और सामरिक विश्वास पर आधारित यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक आपूर्ति संकट और बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और जापान का साथ आना एशिया में एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है।

दिल्ली मेट्रो का यह फैसला- बढ़ जाएगी यात्रियों की परेशानी

संतोष

दुनिया भर के विकसित देशों के विकास की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। बेहतर सड़क और शानदार सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो, ट्रेन आदि) व्यवस्था। कई मायनों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर सरकार द्वारा किए गए खर्च को बड़ा निवेश ही माना जाता है क्योंकि दशकों तक इसका फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को मिलता रहता है। भारत जैसे देश के लिए बेहतर, सुगम और तेज रफ्तार वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो और भी जरूरी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस के आयात पर ही खर्च होता है। तमाम दावों के बीच कड़वी सच्चाई तो यही है कि भारत पेट्रोल–डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और हमारी निर्भरता किस हद तक है, इसका अंदाजा ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई के असर के रूप में हम सबको दिख ही गया है। भारत के लगभग हर शहर में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है लेकिन सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था के कारण लोग उससे भी ज्यादा तेजी से पर्सनल गाड़ियां खरीदते हैं और नतीजा हर तरफ ट्रैफिक जाम यानी पेट्रोल–डीजल और गैस की बर्बादी। दिल्ली में भी मेट्रो का तेजी से विस्तार तो हो रहा है लेकिन यह दिल्ली की जरूरतों के लिहाज से अभी भी काफी पीछे है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नकारते हुए दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत के समय ही यह फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों को रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं। लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी शायद यह भूल गए हैं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन यात्रियों के प्रति है जो उन्हें महंगा किराया देकर मेट्रो में सफर करते हैं। ये अधिकारी, यह भी भूल जाते हैं कि ये भारत है, जहां नैतिकता से जुड़े मुद्दों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने अब यह फैसला किया है कि वो यात्रियों को अब विज्ञापन सिर्फ दिखाएगा ही नहीं बल्कि सुनाएगा भी। यानी जब आप मेट्रो के अंदर सफर करते समय, यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है ताकि आप अपने स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर सकें तो इस बीच आपको दिल्ली मेट्रो अलग–अलग कंपनियों के विज्ञापन सुनने को मजबूर कर देगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपने नॉन–ऑपरेशन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि कंपनियों के ऑडियो विज्ञापन से मेट्रो के अंदर होने वाली जरूरी घोषणाओं जैसे– श्अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, दरवाजों से हटकर खड़े रहें, यह ट्रेन कहां तक जाएगीश पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। आपको बता दें कि, वर्तमान में भी दिल्ली मेट्रो की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मेट्रो ऑपरेशन यानी इसपर सफर करने वाले यात्रियों से ही आता है। जबकि अन्य कामों यानी गैर ऑपरेशनल गतिविधियों से कुल कमाई का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही आता है जिसमें हर तरह के विज्ञापन (स्टेशनों के नाम तक बेचना शामिल है) शामिल हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क, एटीएम और पार्किंग से भी कमाई होती है। जब यात्री खचाखच भरे मेट्रो में (अगला स्टेशन जानने के लिए) डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं देख पाता है, तब मेट्रो हमें विज्ञापन सुनाना चाहता है। लेकिन यह शायद पहला मामला नहीं है जब दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने ऐसा फैसला किया हो। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसलों की तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक सिंपल सा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया था, जिसे यात्री बड़ी ही आसानी से किसी भी स्टेशन से बनवा सकता था और खराब होने पर लौटा भी सकता था। अब मेट्रो ने बैंक से जुड़े कार्ड को थोपने के लिए साधारण वाला स्मार्ट कार्ड छापना ही बंद कर दिया है। प्लास्टिक वाला पुराना टोकन बंद करके, कागज वाला देने लगे हैं जिससे हर स्टेशन के कस्टमर केयर पर आपको कागजों का ढ़ेर नजर आएगा। मेट्रो ने नहीं ले जाने वाले सामानों की लंबी–चौड़ी लिस्ट जारी कर रखी है लेकिन उन्हें स्टेशनों पर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में कोई खतरा नजर नहीं आता। हद तो तब हो जाती है जब ये अपने स्टेशनों पर बड़े–बड़े होर्डिंग लगाकर कंडोम का भी विज्ञापन करते नजर आते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को यह बताया जाए कि इसके गठन का मूल उद्देश्य पूरी दिल्ली को जोड़ना था एवं है(अब तो इसमें छब्ब का इलाका भी शामिल हो गया है) और यात्रियों को तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था देना है। अभी भी दिल्ली एनसीआर का काफी बड़ा इलाका मेट्रो की सुविधा से वंचित है। जिसमें से कई रूट तो दिल्ली मेट्रो के लिए काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प, विश्व कप और राजनीति का खेल

राजेश

अमेरिका–ईरान तनातनी की जड़ में तेल संसाधनों पर कब्जा और मिडिल ईस्ट पर प्रभुत्व कायम रखने के साम्राज्यवादी इरादे भी काम करते हैं। 1900 के दशक से एंग्लो–ईरानियन तेल कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम रखा था। 1953 में मोहम्मद मोसादेह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईरान में ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध तेज हो गया। मेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हो चुका है लेकिन विश्व कप फुटबॉल पर उसकी लंबी और गहरी छाया साफ दिखाई पड़ती है। मौजूदा विश्व कप कई मायनों में अलग है। यह पहला विश्व कप है जिसकी मेजबानी तीन देश–अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। 48 टीमें 104 मैचों में हिस्सा ले रही हैं। कनाडा, मेक्सिको के हिस्से में 13–13 मैच आए हैं और बाकी 78 मैचों का मेजबान अमेरिका है। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एमबापे, नार्वे के एर्लिंग हालैंड जैसे चमकते सितारों ने अपना दबदबा दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैदान से बाहर अलग तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं।ट्रम्प ने ईरान से आए अतिथियों के लिए शिष्टाचार और कूटनीति के तौर–तरीकों को ताक पर रख दिया है। वे टूर्नामेंट के दौरान भी अपने इमिग्रेशन एजेंडा को जोर–शोर से लागू कर रहे हैं। राष्ट्रपति यह सब उस देश में कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया से आकर लोग बसे हैं। शायद अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश हैं जहां इतनी ज्यादा नस्लों, धर्मों और

संस्कृतियों के लोग मिलेंगे। वहां किसी कोने में यूरोप तो कहीं एशिया तो कहीं अफ्रीका महाद्वीप सहित दुनिया के सभी देशों के लोग मिल जाएंगे। अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने में उसकी बहुलता की निर्णायक भूमिका है। ट्रम्प इस पर पानी फेरने की कोशिश में जुटे हैं।11 जून को पहले मैच की व्हिसल बजने से पहले ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। कई टीमों के खिलाड़ियों और दर्शकों को कस्टम्स, इमिग्रेशन (आईसीई) की कड़ी सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन (फीफा) द्वारा चुने गए सोमालिया के रैफरी उमर ओर्टन को मियामी कस्टम्स ने रोका और वापस भेज दिया। 2025 में ओर्टन को अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ रैफरी का दर्जा मिला है। अमेरिकी अधिकारियों ने ओर्टन को प्रवेश न देने का अस्पष्ट कारण बताया कि अवांछनीय लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस अपमान की अफ्रीका में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इसके अलावा सेनेगल, उजबेकिस्तान के खिलाड़यों को अकारण जांच से गुजरना पड़ा है।सबसे अधिक परेशानियां ईरान की टीम के सामने आई थी। अमेरिका से उसका टकराव कदम–कदम पर नजर आया है। इसकी शुरुआत 2025 में हो गई थी। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वीजा नहीं देने के बाद दिसंबर में ड्रा की घोषणा होने पर ईरान ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। बाद में ईरान ने टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लिया। उस वक्त अमेरिका–ईरान युद्ध शुरू नहीं हुआ था। वैसे, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास है। कई कारणों से ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाओं का जोर रहा है। अमेरिका–ईरान तनातनी की जड़ में तेल संसाधनों पर कब्जा और मिडिल ईस्ट पर प्रभुत्व कायम रखने के साम्राज्यवादी इरादे भी काम करते हैं। 1900 के दशक से एंग्लो–ईरानियन तेल कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम रखा था। 1953 में मोहम्मद मोसादेह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईरान में ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध तेज हो गया। मोसादेह ने तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर अमेरिका और ब्रिटेन को जबर्दस्त धक्का लगा। 1957 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीईए ने मोसादेह का तख्ता पलट दिया। सीआईए की मदद से शाह रजा पहलवी ईरान के शाह बन गए। राजशाही के खिलाफ 1978–79 में भीषण क्रांति की शुरुआत हो गई। लाखों लोग शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शाह को ईरान से भागकर अमेरिका में शरण लेना पड़ी थी। 1979 में धार्मिक नेता अयातुल्ला खोमैनी की अगुआई में नई सरकार बनी। कई मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच संवाद का सिलसिला चलता रहा है। इस बीच ईरान ने परमाणु तकनीक हासिल कर ली। वह एटम बम बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। लंबी बातचीत के बाद 2013 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गति धीमी करने के वास्ते एक समझौते पर दस्तखत हुए। हालांकि, ट्रम्प ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल में करार को एकतरफा तौर पर रद्द कर दिया। राष्ट्रपति जार्ज बुश ने तो ईरान को आतंकवाद की धुरी घोषित कर रखा था। ट्रम्प के शासनकाल में दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ी है। 2025 में ओमान में अमेरिका–ईरान शांति वार्ता के बीच इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। इस तनाव का खामियाजा ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका–ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि ईरानी टीम का रास्ता आसान होगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका है। न्यूजीलैंड से 2–2 की बराबरी के बाद ईरानी टीम को उनके कार्यक्रम में बदलाव की सूचना मिली। उन्हें लॉस एंजिल्स में रात गुजारने की बजाय अमेरिका की सीमा के पास मेक्सिको के तिजुआना स्थित अपने ट्रेनिंग कैम्प में लौटने के लिए कहा गया। मैच रात 8 बजे खत्म हुआ था। मेक्सिको के लिए उनकी फ्लाइट रात 11 बजे थी। टीम के हेड कोच आमिर गेनलेनोएल की गुस्से से भरी प्रतिक्रिया आई कि समूचे वर्ल्ड कप में हमारी टीम सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित रही है। विश्व कप से बाहर होने के बाद ईरानी टीम के मैनेजमेंट ने उनके साथ हुए व्यवहार पर निराशा जताई है। यों भी टूर्नामेंट में ईरान की हिस्सेदारी को लेकर देश में विभाजन की स्थिति है। अमेरिका से टकराव को देखते हुए ईरान में बहुत लोग नहीं चाहते थे कि टीम विश्व कप में भाग ले। इसकी तस्वीर ईरान के मैचों में देखने मिली है। लॉस एंजिल्स में लगभग एक लाख ईरानी रहते हैं। वहां मैच के दौरान कुछ ईरानी दर्शक टीम के समर्थन में बैनर लहरा रहे थे तो कुछ लोगों ने ईरान में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की मांग करने वाले सैकड़ों लोगों की हत्याओं पर वर्तमान सरकार का विरोध किया है। ऐसे लोग टीम को दमनकारी शासन का प्रतिनिधि मानते हैं।

जौनपुर में 15 जुलाई तक चलेगा 'मिशन सेफ फ्यूचर', स्कूल वाहनों की होगी सघन जांच

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान 'मिशन सेफ फ्यूचर' चलाएगा। अभियान के तहत जनपद में संचालित सभी स्कूल वाहनों की सघन जांच की जाएगी। बिना फिटनेस, परमिट अथवा सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अजीत सिंह ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे 7 जुलाई तक अपने विद्यालयों में संचालित सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों को नियमानुसार अद्यतन करा लें। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों की जानकारी रखने और केवल मानक पूरे करने वाले वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। आरटीओ ने बताया कि 7 जुलाई के बाद परिवहन विभाग, पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच करेगी। जांच के दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ चालान, सीज सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बार–बार निर्देश और चेतावनी के बावजूद यदि कोई विद्यालय बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों का संचालन करता पाया गया, तो ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित सक्षम अधिकारियों को भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से अभियान को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो।

कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई परीक्षा, 60 जिलों के 955 केंद्रों पर हो रहा आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी–2026) गुरुवार से प्रदेशभर में कड़ी सुरक्षा और सघन निगरानी के बीच शुरू हो गई है। तीन दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर कुल पांच पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के पहले दिन सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। बायोमेट्रिक सत्यापन, रेटिना स्कैन, आधार कार्ड की जांच और सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रदेशभर में फिलहाल परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार इस वर्ष परीक्षा में कुल 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 17,67,180 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश तथा 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। परीक्षा में 1,85,791 सेवारत शिक्षक और 18,08,870 नए अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्राथमिक स्तर के लिए 3,88,179,

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,16,436 तथा दोनों स्तरों के लिए 3,95,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को पांच पालियों में किया जा रहा है। दो जुलाई को उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा, तीन जुलाई को पहली पाली में उच्च प्राथमिक तथा दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी, जबकि चार जुलाई को पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की घटना को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त की गई है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। कई कोचिंग संचालकों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे गए हैं तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वर्ष 2021 में टीईटी प्रश्नपत्र लीक होने की घटना से सबक लेते हुए इस बार बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

विक्रमादित्य तिराहे पर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित विक्रमादित्य तिराहे के पास मंगलवार दोपहर एक युवक ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को तुरंत सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर करीब 1रू20 बजे की है। पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान कन्नौज जनपद के सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम कांकरकुई निवासी 25 वर्षीय सुमित महाराज पुत्र स्वर्गीय जयसिंह (वैश्य ठाकुर) के रूप में बताई। उसके साथ संतोष कुमार (65 वर्ष) पुत्र खुशी लाल तथा रीता (45 वर्ष) पत्नी संतोष भी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक आत्मदाह का प्रयास केवल सुमित महाराज ने किया था।

राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच पर राजेंद्र पाल गौतम ने उठाए सवाल, बोले– बड़े लोगों को बचाया जा रहा है

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को जौनपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका आरोप था कि जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं के प्रभाव में जांच हो रही है, इसलिए न्याय की उम्मीद कम है। गौतम ने आरोप लगाया कि असली आरोपियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी एजेंसियां उपलब्ध हैं, तो निजी सुरक्षा एजेंसी पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण से पहले आए चंदे का भी पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया। उनके अनुसार मंदिर ट्रस्ट के गठन से लेकर उसकी व्यवस्था तक के फैसले केंद्र स्तर पर लिए गए, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए गौतम ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा रहा है और पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, मजदूरों और आम जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाएगी। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक और बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा का मुकाबला करने की क्षमता रखती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में किसी प्रकार की दरार नहीं है और अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।

यूपी बोर्ड के टॉपर्स को 2 साल तक दी जाएगी स्कॉलरशिप, जरूरतमंद छात्रों को फीस में मिलेगी बड़ी राहत

लखनऊ, (संवाददाता)। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था इंडिया लिटरेसी बोर्ड यूपी बोर्ड के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र–छात्राओं को दो साल तक छात्रवृत्ति देगी। यह निर्णय संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया है। बोर्ड की निदेशक संध्या तिवारी ने बताया कि छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र छात्रों को 17 सितंबर को डॉ. वेल्दी फिशर जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत हाईस्कूल के राज्य टॉपर को तीन हजार हर महीने और इंटर के राज्य टॉपर को पांच हजार रुपये हर महीने की छात्रवृत्ति दो वर्ष तक मिलेगी। वर्ष 2026 की हाईस्कूल परीक्षा में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया, जबकि इंटर में शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान पाया। इंडिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेंस अकादमी के विद्यालय स्तर के टॉपर्स को भी इसी योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बोर्ड ने एक ही परिवार के दूसरे बच्चे को शिक्षण शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट देगा। वहीं एकल मां के पहले और दूसरे बच्चे को 30–30 प्रतिशत शुल्क में छूट दी जाएगी।

प्रदेश में 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की होगी भर्ती, राज्य सरकार ने नए पद सृजित करने का लिया निर्णय

लखनऊ, (संवाददाता)। ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों (पंचायत सचिव) के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 4372 पदों के सृजन को हरी झंडी दे गई है। प्रदेश में करीब 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं। इनमें वर्तमान में सिर्फ 16 हजार ग्राम पंचायत अधिकारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 42 हजार ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार के जरिये काम कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक

ग्राम पंचायत में अलग सचिव की तैनाती करना है ताकि पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। नई भर्ती पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था का भार कम होने की उम्मीद है। बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी (वीपीओ) और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के काडर को मिलाकर एकीकृत (यूनिफाइड) काडर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। दोनों संवर्ग पहले की तरह अलग–अलग ही रहेंगे। सरकार का मानना है कि नए पदों के सृजन से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों को योजनाओं एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ के रहीमाबाद में भूमि विवाद ने लिया हिंसक रूप

लखनऊ, (संवाददाता)। रहीमाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी–डंडों और लात–घूंसों से मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान एक पक्ष की ओर से लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग किए जाने की भी सूचना है। हालांकि मेडिकल परीक्षण में किसी को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है।पुलिस के अनुसार, सूचना मिलते ही रहीमाबाद थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रथम पक्ष के राम सिंह यादव, अनिल कुमार और कुलदीप कुमार रावत अपनी भूमि पर पहुंचे थे। वहां पहले से मौजूद द्वितीय पक्ष के घनश्याम यादव, सावित्री, संतोष तथा अन्य लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान अनिल कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से एक राउंड फायर किया। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल परीक्षण में किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है।घटना में घायल सभी लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद भेजा गया। वहां से दोनों पक्षों के एक–एक गंभीर घायल को बेहतर उपचार के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।एहतियात के तौर पर गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, शांति एवं कानून–व्यवस्था सामान्य बनी हुई है तथा पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

3 जुलाई को नगर निगम का 'संपूर्ण समाधान दिवस'

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम लखनऊ नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 3 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन करेगा। इस दौरान शहरवासी अपनी शिकायतें सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।नगर निगम द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में जल निकासी, सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, गृहकर, अतिक्रमण तथा नगर निगम से संबंधित अन्य जनसमस्याओं और शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा।

तीन दिन चलने वाली यूपी टीईटी आज से, 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के 60 जिलों से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी एक लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कुल 955 केंद्रों पर होगी। महाराष्ट्र में टीईटी का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों कोचिंग संचालकों के नंबर निगरानी पर लिए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराने की बात कही। वर्ष 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इसी कारण इस बार एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। सर्वाधिक परीक्षा केंद्र एवं अभ्यर्थियों वाले जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, आगरा तथा जौनपुर शामिल हैं। टीईटी के लिए जौनपुर से सबसे अधिक 67597 और लद्दाख से सबसे कम एक अभ्यर्थी पंजीकृत है। बिहार से 31766, मध्य प्रदेश से 20375, दिल्ली से 16411 और राजस्थान से 12774 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा से 5748, झारखंड से

5635, उत्तराखंड से 2710 और पश्चिम बंगाल से 1909 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इस बारे में निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ अन्य राज्यों से भी आएंगे। ऐसे में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तथा प्रमुख यातायात केन्द्रों पर पर्याप्त सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। परिवहन निगम, रेलवे तथा आवश्यकतानुसार निजी स्थानीय परिवहन संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। परीक्षा के पूर्व एवं पश्चात संभावित भीड़ को देखते हुए प्रभावी यातायात प्रबंधन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बड़ी संख्या में युवाओं के आवागमन के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थों के मूल्य अनावश्यक रूप से न बढ़ाए जाएं।

नगराम पुलिस ने घर में चोरी करने वाले दो शातिर चोर दबोचे

लखनऊ, (संवाददाता)। नगराम थाना पुलिस ने घर में घुसकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी करने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए जेवर, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बेलचा बरामद किया है। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को अनैय्या खरगापुर निवासी अम्बरीश कुमार मिश्र ने तहरीर देकर बताया था कि 28 जून की रात अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए और अलमारी का लॉक तोड़कर नकदी एवं जेवर चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर नगराम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर दो विशेष टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 90 से 100 सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। इसके बाद संदिग्धों की पहचान कर बुधवार को मुखबिर की सूचना पर इंदिरा नहर किनारे डोरिया मोड़ के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नगराम थाना क्षेत्र के दोरिया मजरा हरदोईया निवासी 35 वर्षीय रामचन्द्र तथा मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गौरा निवासी 45 वर्षीय बुद्धिलाल के रूप में हुई है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मजदूरी करने के साथ–साथ बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे। जब उन्हें यह भरोसा हो जाता था कि घर में कोई नहीं है,।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की व्यापक जांच हो, फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं– समाजवादी पार्टी

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन कर फर्जी एवं डुप्लीकेट नाम हटाने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के 1,77,516 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाने की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि इससे विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेंगे।समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम दर्ज हैं। पार्टी के अनुसार, मतदान केंद्र संख्या 142 पर एक मतदाता का नाम छह बार, मतदान केंद्र संख्या 143 पर एक मतदाता का नाम पांच बार तथा अन्य कई मतदाताओं के नाम दो से चार बार तक दर्ज हैं। पार्टी का दावा है कि पूरे शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मौजूद हैं।ज्ञापन में रायबरेली विधानसभा क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां कई मतदान केंद्रों पर एक ही मतदाता के नाम दो–दो बार दर्ज हैं। पार्टी के अनुसार, रायबरेली जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों में 4,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता सूची में शामिल हैं, जिनकी जांच कर नाम हटाए जाने की आवश्यकता है।समाजवादी पार्टी ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मतदान केंद्र संख्या 49, 50, 51, 52 और 53 पर बड़ी संख्या में फर्जी नाम एवं फर्जी पते दर्ज हैं। पार्टी का दावा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर 70 से लेकर 120 से अधिक संदिग्ध प्रविष्टियां मौजूद हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 459 को लेकर भी पार्टी ने आपत्ति जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से लगभग आठ किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग एवं अन्य मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाई होती है। समाजवादी पार्टी ने इस मतदान केंद्र को निकट स्थित मतदान केंद्र संख्या 383, सरियापुर से संबद्ध किए जाने की मांग की है, ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके और मतदान प्रतिशत बढ़े।पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि सिद्धार्थनगर, रायबरेली और वाराणसी में कथित डुप्लीकेट एवं फर्जी मतदाताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सड़क हादसे के बाद गौमांस मिलने के मामले में एक साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। गुडम्बा थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटना और गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े चर्चित मामले में एक वर्ष से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक जांच में बरामद मांस गाय अथवा उसकी संतति का पाए जाने के बाद मुकदमे में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई थीं।पुलिस के अनुसार, 7 जून 2025 को शिवानी विहार, कल्याणपुर निवासी अरुण कुमार पाठक की तहरीर पर गुडम्बा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि विक्रम टेम्पो चालक सूरज ने शराब के नशे में तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में पंकज मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना के दौरान पुलिस को विक्रम टेम्पो से पशु के शरीर के अवशेष बरामद हुए थे। संदेह के आधार पर नमूनों को विधिक प्रक्रिया के तहत मथुरा स्थित फॉरेंसिक जांच प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में बरामद नमूना गाय अथवा उसकी संतति का पाए जाने के बाद विवेचना के दौरान मुकदमे में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 भी जोड़ दी गईं।बुधवार को गुडम्बा थाना पुलिस ने मुकदमे में वांछित आरोपी सूरज पुत्र रामलखन, निवासी रडहुआ टेराखुर्द, थाना देवा, जनपद बाराबंकी को 23 नंबर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष बकरीद के अवसर पर खुर्रमनगर चौराहे के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने अधिक रुपये देने का लालच देकर उससे दो बोरी गौमांस शिवानी विहार स्थित मैकाले क्षेत्र के पास पहुंचाने के लिए कहा था। आरोपी के अनुसार, वह शराब के नशे में अपने विक्रम ऑटो से मांस ले जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई।

विकास प्राधिकरण कार्यालय में नगर विधायक व मेयर की अध्यक्षता मे कोचिंग व लाइब्रेरी संचालकों की बैठक संपन्न

अयोध्या।शुक्रवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता तथा महापौर महान गिरीश पति त्रिपाठी की अध्यक्षता में कोचिंग तथा लाइब्रेरी संचालकों की बैठक संपन्न हुई।इस बैठक में मुख्य रूप से नगर विधायक व महापौर ने वहां पर मौजूद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुराज रंजन, सीएफओ एमपी सिंह तथा डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी से कोचिंग व लाइब्रेरी के संचालको के लिए राहत देने की बात कही।बैठक के दौरान विधायक तथा महापौर कोचिंग तथा लाइब्रेरी संचालकों से अपील किया कि वे भी समय रहते विभाग द्वारा तय किए गए मानक को पूरा कर ले।इस मौके पर उन्होंने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष,सीएफओ तथा डीआईओएस से भी कहा कि मानक ऐसा तय करें जिससे कोचिंग तथा लाइब्रेरी के संचालकों को किसी तरह की परेशानी ना हो वह मानक भी तय कर ले और आप सभी अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित मानक को तय करा पाए।इस मौके पर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने सभी कोचिंग तथा लाइब्रेरी संचालकों को महीने का समय देते हुए मानक को पूरा करने की अपील किया है।वही आज से कुछ दिन पहले सील किए गए कोचिंग संस्थान सोमवार को तभी खुलेंगे जब संबंधित कोचिंग वाला लाइब्रेरी संचालक शपथ पत्र देगे।इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने कहा कि सभी कोचिंग तथा लाइब्रेरी संचालक मानक पर खरे उतरें साथ ही साथ किसी भी संचालक को कोचिंग चलाने तथा लाइब्रेरी खोलने की अनुमति बेसमेंट में कतई नहीं दी जाएगी।इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन तिवारी ने कहा कि कोचिंग तथा लाइब्रेरी मानक के अनुसार ही खोल।बैठक में विकास प्राधिकरण,शिक्षा विभाग,अग्निशमन विभाग इंजीनियर सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।

सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासनध्प्रवर्तन ने बताया है, कि शासन के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान चलाया जाना है जिसे मिशन सेफ फ्यूचर कहा जाएगा। इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जानी है। जिसके अनुपालन में स्कूली वाहनो के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, आज चेंकिग के दौरान 05 स्कूली वाहनो का चालान किया गया तथा 03 स्कूली वाहनो को विभिन्न थानो में निरूद्ध किया गया। जनपद के दक्ष इण्टरनेशनल स्कूल, निकट हरियाली पेट्रोल पम्प शाहाबाद के 13 वाहनों के तथा जय विद्या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, खेतुई लखनऊ रोड हरदोई के 12 एवं न्यू हाईट्स स्कूल, नानक गंज ग्रन्ट लखनऊ के 11 वाहनों के प्रपत्र वैध नहीं हैं, इनके द्वारा अभी तक प्रपत्र वैध नहीं कराए गए है। जनपद हरदोई के समस्त ऐसे स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेसध्परमिटध्बीमाध्प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे अपने स्कूली वाहनों की फिटनेसध्परमिटध्बीमाध्प्रदूषण नवीनीकरण का कार्य तत्काल करा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रधानाचार्यध्विद्यालय संचालकों से भी इस संबंध में अपील की जाती है कि छात्र–छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये अपने–अपने विद्यालयोंध्स्कूलों में स्कूली वाहनों के रूप में संचालित ऐसे स्कूली वाहन जिनकी फिटनेसधबिना परमिटध्प्रदूषण वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन कदापि न होने दें एवं ऐसे वाहन स्वामियों को उन्हें अपनी स्कूली वाहनों की फिटनेसध्परमिटध्बीमाध्प्रदूषण नवीनीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं असुविधा से बचा जा सकें। उन्होंने बताया कि 08 से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जायेगी और बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण आदि सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्ती से चालान कर कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल स्वामित्व में संचालित असुरक्षितध्अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ–साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेंकिग की जायेगी जो बिना बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण, बिना बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानको का उल्लघंन करते हुए स्कूली बच्चो का परिवहन कर रहें है ऐसे वाहनो के चालान की कार्यवाही की जायेगी।

'माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया आम महोत्सव का तीन दिवसीय उद्घाटन'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आम महोत्सव का तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया जिसमें विशिष्ठ अतिथि माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी मंत्री उद्यान कृषि विपणन, कृषि

निर्यात, कृषि विदेश व्यापार जी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में जनपद हरदोई से 150 कृषको द्वारा प्रतिभाग किया गया। महोत्सव में कृषकों द्वारा लगभग 800 से अधिक आम की वैराइटी लगाए गई । इस अवसर पर जनपद हरदोई से जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्रा एवं सहायक उद्यान निरीक्षक अजय कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

दिल्ली से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो ट्रक से भिड़ी, 3 की मौत- 4 गंभीर

गोरखपुर, (संवाददाता)। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया निवासी एक ही परिवार पर बुधवार देर रात लौटते समय दर्दनाक हादसे ने कहर बरपा दिया। अयोध्या–लखनऊ हाईवे पर मुबारकगंज के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने–सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना से पूरे कस्बे में शोक व्याप्त हो गया। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया निवासी दुर्गेश गुप्ता उर्फ मुन्नू गुप्ता (55) अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी, बड़े बेटे अभिषेक गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता तथा अन्य परिजनों के साथ दिल्ली में अपनी छोटी बेटी के घर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिवार बुधवार शाम को दिल्ली से स्कॉर्पियो से वापस सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हुआ। देर रात अयोध्या–लखनऊ हाईवे पर मुबारकगंज के पास उनकी स्कॉर्पियो की एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि दुर्गेश गुप्ता (55), उनकी बेटी पिंकी गुप्ता (30) तथा नातिन परी गुप्ता (8) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पत्नी विजयलक्ष्मी गुप्ता (50), पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता (24), नाती गोलू गुप्ता (12) तथा दामाद राधेश्याम गुप्ता (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों और क्षेत्रवासियों को मिली, पूरे इलाके में मातम छा गया। बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। शोक व्यक्त करते हुए स्थानीय व्यापारियों ने अपनी–अपनी दुकानें बंद रखीं।

अमरनाथ यात्रा के लिए भारती एयरटेल ने मजबूत की कनेक्टिविटी, किया नेटवर्क कवरेज का विस्तार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारती एयरटेल ने आज अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अपने मोबाइल नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। इस पहल से क्षेत्र में तीर्थयात्रियों, सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय प्रशासन के लिए कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया है। बालटाल में अपनी मौजूदा उपस्थिति के अलावा, एयरटेल ने चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप और बेताब घाटी में नेटवर्क साइटस तैनात कर महत्वपूर्ण पहलगाम मार्ग पर नेटवर्क कवरेज स्थापित किया है। इसके साथ ही पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह तैनाती संबंधित सरकारी प्राधिकरणों और स्थानीय प्रशासन के साथ आपसी समन्वय में की गई है। विस्तारित नेटवर्क कवरेज से विश्वसनीय वॉयस और डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, आपातकालीन संचार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा लाखों तीर्थयात्रियों के लिए डिजिटल पहुंच बेहतर होगी। जम्मू–कश्मीर में भारती एयरटेल के सीओओ, विक्रम आरएस, ने कहा, ष्एयरटेल में हम सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में भी लोगों, समुदायों और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम और बालटाल, दोनों मार्गों पर हमारे नेटवर्क का विस्तार जम्मू–कश्मीर में हमारे निरंतर निवेश का प्रमाण है। साथ ही, इस महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, सुरक्षा बलों और प्रशासन को हर समय विश्वसनीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। सबसे मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में भी एयरटेल का लगातार नेटवर्क विस्तार देश में कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करने और भारत के डिजिटल बदलाव को नई गति देने के उसके निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है।

विकास प्राधिकरण अयोध्या कार्यालय की सीढी अचानक टूटी

अयोध्या। कोचिंग,लाइब्रेरी,प्रतिष्ठानों तथा दूसरों की बिल्डिंगों का मानक तय करने वाली विकास प्राधिकरण अयोध्या कार्यालय की सीढी अचानक गिर गई।घटना के समय नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व कई कोचिंग व लाइब्रेरी संचालक मौजूद रहे।लेकिन कोई इस हादसे में घायल नहीं हुआ।बताते चले कि घटना से थोड़ी देर पहले इसी कार्यालय में नगर

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता तथा महापौर गिरीशपति त्रिपाठी की अध्यक्षता में कोचिंग संचालकों व लाइब्रेरी प्रबंधकों के साथ एक बैठक की गई थी।बैठक के बाद यह हादसा हुआ।सीडी टूटने से कार्यालय परिसर में अफरा–तफरी का माहौल बन गया। यहां पर मौजूद तथा अन्य लोगों का एक ही सवाल रहा जब निर्माण मानकों की निगरानी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय में हुई इस घटना ने भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गीडा में अवैध होटलों पर शिकंजा, 18 को नोटिस जारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में लंबे समय से चल रहे अवैध होटल कारोबार पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। औद्योगिक विकास के लिए बनाए गए इस क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रहे होटलों को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। नतीजतन गीडा प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अवैध निर्माण और संचालन करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। गीडा ने ऐसे 18 होटल मालिकों को नोटिस जारी किया है। जांच के दौरान गीडा प्रशासन ने सेक्टर–22, ट्रांसपोर्टनगर समेत अन्य इलाकों में संचालित ऐसे 18 होटलों को चिह्नित किया है, जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और आवश्यक अनुमति के चल रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन होटलों के पास न तो गीडा से स्वीकृत नक्शा है और न ही सराय अधिनियम के तहत जरूरी पंजीकरण। कई होटलों में अग्निशमन सुरक्षा के मानक भी पूरे नहीं किए गए हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक भूखंडों का इस्तेमाल नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इससे न सिर्फ गीडा की मूल अवधारणा प्रभावित हो रही थी, बल्कि क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी बढ़ रही थीं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी। गीडा प्रशासन ने फिलहाल 18 होटल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। शासन के निर्देश पर कराई गई जांच में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए होटल निर्माण और संचालन की पुष्टि हुई है। संबंधित सभी होटल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मई तक रेलवे स्टेशन पर बन जाएगा नया एफओबी

गोरखपुर, (संवाददाता)। रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी फुट ओवरब्रिज टू लेन में बनाया जाएगा, एक लेन मई तक बनाकर यात्रियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि दूसरा लेन सितंबर तक तैयार होगा। इसके बाद दूसरे एफओबी का निर्माण शुरू होगा। दोनों एफओबी की चौड़ाई तीन मीटर होगी। रेलवे स्टेशन पर तीन एफओबी थे, जिसमें एक जर्जर हो गया था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। अब स्टेशन के पुनर्विकास योजना के तहत दो एफओबी बनाए जाएंगे। एक जीआरपी थाने के पुराने भवन के पास बनाया जा रहा है। फाउंडेशन का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। महाप्रबंधक ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य तेज कराने के निर्देश दिए हैं।

गुलरिहा में फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की पैतृक भूमि हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में लंगड़ी गुलरिहा निवासी दिलीप गुप्ता की तहरीर पर सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार सुरेश चंद गुप्ता समेत छह नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिलीप गुप्ता ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के ही रहने वाले सुरेश चंद नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं। आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो के पद पर कार्यरत रहते हुए सुरेश चंद ने अपनी पत्नी शारदा देवी, भाभी शांति देवी और भांजे सुभाष के नाम पीड़ित की जमीन का फर्जी पट्टा करवा लिया। पीड़ित का कहना है कि जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन हुआ तब आरोपियों ने सुनवाई के दौरान फर्जी खतौनी, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी अभिलेख तैयार कर उन्हें सरकारी कार्यालयों और न्यायालय में प्रस्तुत किया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस प्रकरण में सुरेश चंद गुप्ता, उसकी पत्नी शारदा देवी, भाभी शांति देवी, रामनैन, सुभाष, लालचंद तथा अन्य सहयोगियों की संलिप्तता है। आरोप है कि सभी ने मिलकर फर्जी परिवार रजिस्टर, फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की। पीड़ित दिलीप गुप्ता का आरोप है कि इस फर्जीवाड़े के माध्यम से न केवल उसकी पैतृक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई, बल्कि उसे मानसिक और आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचाई गई। लगातार न्यायालय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। गुलरिहा थाना प्रभारी गुलरिहा इत्यानंद पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और प्रयागराज छात्रावास फाइनल में

गोरखपुर, (संवाददाता)। खेल विभाग की ओर से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय सब जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। इनमें वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और प्रयागराज छात्रावास ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। शुक्रवार को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहला क्वार्टर फाइनल मैच प्रयागराज छात्रावास व मुरादाबाद मंडल के मध्य खेला गया। इसमें प्रयागराज ने 25–16, 25–16 से जीत दर्ज की। दूसरा क्वार्टर फाइनल स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर व अयोध्या के बीच खेला गया। इसमें गोरखपुर ने 25–17, 25–12 से जीत दर्ज की। तीसरा क्वार्टर फाइनल गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ व गोरखपुर मंडल के मध्य खेला गया। इसमें लखनऊ ने 2–0 से जीत दर्ज की। अंतिम क्वार्टर फाइनल देवरिया छात्रावास व आगरा के मध्य खेला गया। इसमें देवरिया ने 2–1 से जीत दर्ज की। को 25–12, 25–23, 25–22 से, दूसरे में प्रयागराज छात्रावास ने देवरिया को 25–27, 17–25, 26–24 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

एमएमएमयूटी के 87 छात्र-छात्राओं को मिली नौकरीद

गोरखपुर, (संवाददाता)। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 87 छात्र–छात्राओं को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिला है। इन छात्रों को तीन से नौ लाख रुपये तक का वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया है। वर्तमान सत्र में कैंपस प्लेसमेंट पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 700 पहुंच गई है। एमएमएमयूटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के चेयरमैन प्रो. वीके द्विवेदी ने बताया कि 'टीसीएस' में कुल 33 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिला है। इन्हें तीन से नौ लाख तक का पैकेज मिला है। आदित्य बिड़ला ग्रुप में 17, एनपीसीएल (नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) में 12 छात्रों को सात लाख, एलएंडटी में तीन को 6.8 लाख रुपये का पैकेज मिला है। इसके अलावा सात अन्य कंपनियों में भी प्लेसमेंट मिला है। प्लेसमेंट सेल की समन्वयक सुकन्या पांडेय ने बताया ।

मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग केंद्र का हुआ शुभारंभ

भदोही, (संवाददाता)। जिले के आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण एवं निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को अभ्युदय कोचिंग केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने फीता काटकर मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग केंद्र का शुभारंभ किया। कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य ऐसे मेधावी युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक सीमाओं के कारण उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते। कोचिंग से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अध्ययन, अनुशासन, समय का सदुपयोग तथा सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। मौके पर उप जिलाधिकारी (न्यायिक) शिव प्रकाश, बीएएस शिवम पांडेय, डीआईओएस अंशुमान, जिला समाज कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नोडल अधिकारी पंकज पटेल आदि मौजूद रहे।आदि मौजूद रहे।

पांच साल रोशन करने की गारंटी डेढ़ साल में ही अंधेरे का कब्जा

भदोही, (संवाददाता)। नगर के सुंदरीकरण के लिए लगाई गई स्ट्रीट लाइटें डेढ़ साल के भीतर ही खराब होने लगी हैं। नगर विकास योजना के तहत करीब दो करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई 250 स्ट्रीट लाइटों में से करीब 35 फीसदी खराब हैं। इन लाइटों की गारंटी पांच वर्ष की बताई गई थी, लेकिन ये डेढ़ साल भी नहीं चल सकीं। नगर में लगी अधिकतर लाइटें अब शोपीस बनकर रह गई हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव मार्ग पर लाइटें बंद होने से अंधेरा रहता है। गोपीगंज जिले का प्रमुख व्यावसायिक नगर है। वाराणसी–प्रयागराज हाईवे पर स्थित होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है।

कड़ी सुरक्षा के बीच चंदौली में 12 केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा, जांच के बाद अभ्यर्थियों की एंट्री

वाराणसी, (संवाददाता)। चंदौली जिले में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। परीक्षा जिले के 12 निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुबह आठ बजे से ही अभ्यर्थियों की केंद्रों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। परीक्षा केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का मिलान करने के बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने मेटल डिटेक्टर से जांच की, वहीं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को बाहर ही जमा कराना पड़ा। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रही। केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दी गई। परीक्षा की निगरानी के लिए सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण करते रहे, ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान अभ्यर्थियों के साथ पहुंचे उनके परिजनों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे परिजन तेज धूप के कारण छांव की तलाश में इधर–उधर भटकते नजर आए। कई लोग पेड़ों और दुकानों के सामने खड़े होकर समय बिताते रहे, जबकि कुछ लोग पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव में परेशान दिखे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।